केजरीवाल के स्कूल.....

पेज एक का शेष

कुछ बच्चों से बात करने पर पता चला कि अब स्कूल में एक्स्ट्रा करीकुलम एक्टिविटीज भी होती हैं। नवीं कक्षा के छात्र नवीन ने बताया कि पहली बार उन्हें आगरा और कुछ अन्य स्कूल के उनके दोस्तों को एजुकेशनल ट्रिप पर घुमाने ले जाया गया जिसमे उनको सीखने और देखने के साथ-साथ बहुत मजा भी आया।

नवीन के ही दोस्त प्रदीप और हाकम ने कहा कि पहले तो वे स्कूल से बंक मारते थे पर आजकल नया-नया मजेदार काम भी होया करें स्कूल में तो हम इस बहाने आ जाते हैं। पढने में तो कोई मजा ना आता पर आजकल खेलकूद भी भोत हो रही है। कई अभिभावकों ने स्कूल पर संतुष्टि जाहिर की तो कुछ की यह शिकायत भी थी कि अब मास्टर बच्चों को मारते नहीं इसलिए बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं।

स्कूल में बतौर गेस्ट टीचर प्रिया ने केजरीवाल सुधारों का एक और पक्ष रखा। उनका कहना है कि यूँ तो इस सरकार में पिछले 3 साल से उनको हटाया नहीं गया पर रोजगार की सुरक्षा फिर भी नहीं है। जहां सरकार इतने काम कर रही है वहाँ क्या सरकार नए कामों के लिए नया स्टाफ नहीं ले सकती? पढ़ाने के अतिरिक्त ज्यादातर प्रशासनिक कार्य भी हमीं गेस्ट टीचर्स से कराया जा रहा है। उपर से सिलेबस खत्म कराने का दबाव अलग। इस बीच रिजल्ट यदि अच्छा नहीं आया तो उसकी जवाबदेही भी हमारी ही।

मीनू, एक अन्य गेस्ट टीचर ने बताया कि परमानेंट टीचर पर वैसा अतिरिक्त बोझ नहीं है जैसा उन जैसों पर। यदि बच्चा 10 दिन स्कूल न आये तो उसका नाम काट दिया जाता है परंतु वही बच्चा माफी मांगता हुआ वापस नाम लिखवाना चाहे तो उसे दोबारा दाखिला मिल जाता है। ऐसे में हाजिरी को लेकर बच्चों में डर का अंश समाप्त हो गया है। अब जब बच्चा पूरी क्लासेज ही नहीं लेता तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा?

क्योंकि आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता तो इसका फायदा उठा कर बच्चे ही नहीं अभिभावक भी पढाई को लेकर गंभीर नहीं दिखते। ऐसे बच्चे जैसे ही नवीं में जाते हैं तो फेल होते हैं। ऐसे सिस्टम के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और साथ ही दोनों पक्षों (शिक्षक और छात्र) में जिम्मेदारी का अभाव आता जा रहा है।

30 वर्षीय शिल्पी ने अपना घोर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि गेस्ट टीचर्स को प्रति दिन के हिसाब से पैसा दिया जाना गलत है। यदि एक दिन किसी कारणवश हम ना आ सके तो उस दिन का पैसा नहीं मिलता जो 1000 रुपये के लगभग है। ऐसे में सरकार की ये बात बिल्कुल बेमानी है कि न्यूनतम राशि 30000 दे रहे हैं। तीस हजार तो होता ही नहीं किसी महीने में क्योंकि रविवार और दो शनिवार तो हमेशा बंद रहता है। यदि कहीं हम बीमार पड़ें और स्कूल न जा सके तो वो पैसा भी कटता है।

इन सभी बातों को सम्मिलित रूप देकर एक खांचे में संजोने का प्रयास यदि किया जाए तो शायद केजरीवाल के स्कूल मॉडल का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। सरकार स्कूल के नाम पर किसे स्कूल मान रही है? सिर्फ एक बढ़ी बिल्डिंग और विदेशी प्रशिक्षण को ही? या शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल हर शिक्षक, सफाई कर्मचारी, गार्ड, चपरासी इन सबको भी अभिन्न अंग माना गया है? यदि हां तो फोर्थ क्लास के सपोर्ट स्टाफ के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है, दिल्ली सरकार इसका कोई ढोल पिटता नहीं दिखा।

ज्यादातर सरकारी अध्यापक या कर्मचारी कामचोर हैं, ऐसा मानने वाली सरकार अपनी असल जिम्मेदारी से पिंड छुड़ाने का मार्ग खोज लेती है। क्यों हम मान लेते हैं कि सरकारी आदमी कामचोर है जबकि उसी सांस में गेस्ट टीचर से आप प्रशाशनिक कार्य तक लेते हैं जबकि न ही उसके काम करने के घंटे तय हैं न ही उसे मिलने वाला मानदेय।

स्कूल एक संस्था है जो अपने सभी सहयोगियों और पात्रों के उचित प्रबंधन के बिना नहीं चल सकता। अध्यापक और अन्य सभी सहयोगी घटक यदि किसी भी तरीके के दबाव में काम कर रहे हैं तो उस दबाव का असर अंतिम परिणाम पर बिल्कुल दिखेगा।

इसी प्रकार बच्चे को आठवीं तक फेल न करना और किसी भी जिम्मेदारी का बोध न होने देना घातक हो सकता है। केंद्र सरकार का तर्क है कि आत्महत्या की घटनाये इससे कम होंगी। परन्तु क्या सचमुच में बच्चा आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि वह फेल हो गया? नहीं, आत्महत्या का मूल कारण पारिवारिक और सामजिक रूप से बच्चे पर डाला जाने वाला दबाव है। तो इसमें एक और पक्ष जुड़ता है वो है समाजिक बदलाव और स्कूल के नीति निर्धारकों की सोच में बदलाव।

हम और आप सभी ने अपने जीवन में ये अवश्य अनुभव किया होगा कि अध्यापक जो इसी समाज का उत्पाद है, भी बच्चे में फेल होने के भय को उसकी प्रतिष्ठा से जोड़ते मिल जाते हैं। और यही प्रतिष्ठा नामक मृगतृष्णा आगे चल कर आत्महत्या जैसे कृत में विस्फोटित होती है। इसलिए आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन की नींव रखने की।

अच्छी आधारभूत संरचना का निर्माण कर केजरीवाल ने एक सुखद आगाज कर दिया है और इसे बिस्मिल्लाह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा। इस काम से जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूल की बिल्डिंग और संरचना को लेकर बच्चे के मन में उत्पन्न होने वाले कुंठित भाव पर चोट हुई है वही निजी स्कूल से चमक-दमक की बराबरी ने बच्चों और अभिभावकों के आत्मविश्वास को भी मजबूत किया ही होगा।

यहाँ से आवश्यकता है अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूप और ट्रेंड होने की। साथ ही सरकार अपने स्कूल के हर अंग को दबाव मुक्त करने की। प्रशासनिक कार्यों के लिए नया स्टाफ भर्ती किया जाए। प्लान में काफी त्रुटियाँ होने के बावजूद कहना होगा कि केजरीवाल सरकार ने कम से कम आज के मंदिर-मस्जिद वाली राजनीति में स्कूल को जगह देकर एक वैकल्पिक राजनीति का चिराग जरूर रोशन किया है। बस अंत भी ऐसे ही मुद्दों पर होगा इसका शक बना हुआ है क्योंकि यदा कदा केजरीवाल भी कांवड़ और तीर्थयात्राओं के नाम पर आरती करना नहीं चूकते।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

देश के आधे एटीएम बन्द

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 02-08 दिसम्बर 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, साहित्यिक व अर्थिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। गत लोक सभा चुनाव के समय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, फ़सलों का बीमा करने और फ़सलों का उचित दाम दिलाने के शब्जबाग दिखाये। किसानों को 'अन्नदाता' कहकर लुभाने का प्रयास किया, परंतु किसानों की दशा सुधारने के लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। पी. साईनाथ ने खुलासा किया कि मोदी सरकार की फ़सल बीमा योजना राफ़ेल से भी बड़ा घोटाला है जिसमें बिना किसी निवेश के अम्बानी की रिलायंस बीमा कम्पनी ने करोड़ों रुपयों का लाभ कमाया जबकि अधिकांश किसानों को कुछ नहीं मिला, इसके बावजूद बीमा करवाने के लिये किसानों को मजबूर किया गया। परेशान होकर किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये दिल्ली तक चार बार कूच किया, लेकिन 29-30 नवम्बर 2018 का किसान मुक्ति मार्च अपने आप में एक एतिहासिक विरोध प्रदर्शन था जिसमें देश भर के 206 किसान संगठन 'अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति' के तत्वधान में इकट्ठे हुए। इसकी प्रमुख विशेषता थी कि यह शांतिपूर्ण और अहिंसक मार्च रहा और भु-स्वामी, मंझोला व छोटा किसान, बटाईदार व खेतीहर मज़दूर सब अपनी मांगों को मनवाने के लिये एकजुट हुये। इस किसान मुक्ति यात्रा को दिल्ली के मध्य वर्ग-डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी, पत्रकार आदि का भी भरपूर समर्थन मिला जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण व एतिहासिक घटना है। 'मामला सिर्फ़ किसान या ''अन्नदाता'' का नहीं है, मामला पूरे खेती के ढांचे का है', 'बात' राम के घर की नहीं बल्कि ''रमुआ'' के जमीन की है, 'सम्भल जाओ दिल्ली...किसानों को बार-बार मत बुलाओ...वरना तुम्हारे तख्त उछाले जायेंगे...मुखौटे उतारे जायेंगे', बीजेपी सरकार में किसान हुआ बेहाल, पूंजीपति हुआ मालामाल' तथा 'किसान मुक्ति यात्रा-सरकार के दरवाजे पर किसान की दस्तक' में किसान यात्रा के विभिन्न पक्षों का सटीक विश्लेषण किया गया है।

भारतीय प्रजातांत्रिक दलों में एक नई ताकत व आशा का संचार हुआ और देश में 23 राजनीतिक दलों ने किसान संघर्ष समिति को मांगपत्र को समर्थन दिया। उनकी प्रमुख मांगे हैं-संसद का 21 दिन का विशेष किसान अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो, कर्ज़ा मुक्ति बिल पास किये जायें तथा फ़सल की लागत का हिसाब बेहतर पद्धति से किये जाये जिससे लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत बचत सुनिश्चित हो जाये। यह किसान मुक्ति मार्च केवल कर्ज़ा माफ़ी आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय प्रजातंत्र में राष्ट्रीय असंतोष की लहर थी। प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर ने शब्द ''सिंहासन खाली करो जनता आती है'' इस किसान मुक्ति यात्रा पर सही चरितार्थ होते हैं।

स्थानीय जवाहर लाल नेहरू कॉलेज (नेहरू कॉलेज) के 600 से अधिक विद्यार्थियों पर आवश्यक कागजात जमा न कराने के नाम पर 5000 रुपये का जुर्माना लगने से नेहरू कॉलेज के प्रशासन की नालायकी व लापरवाही जाहिर होती है,जिसका 'गरीब छात्रों के अभिभावकों की जेब को निशाना बनाया नेहरू कॉलेज प्रशासन ने' में खुलासा किया गया है। सभी विद्यार्थियों का यह दावा है कि उन्होंने फर्म जमा करने के साथ ही जरूरी कागजात जमा करा दिये थे तो सम्बन्धित क्लर्क की जवाबदेही बनती है कि उसने रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं लिये? यह जुर्माना विद्यार्थियों पर नहीं, बल्कि कॉलेज की प्रिंसिपल व सम्बन्धित क्लर्क पर लगना चाहिये।

नेहरू कॉलेज में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। इस कॉलेज समेत हरियाणा के लगभग सभी सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जिससे अक्सर छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है, जिसका 'जुर्माना तो सरकार के शिक्षा प्रबन्धकों पर लगना चाहिये' में विवेचन किया गया है। कॉलेज का प्रमुख भवन जर्जर घोषित हो चुका है। पढने और बैठने की बुनियादी व्यवस्था उपलब्ध न कराने पर खट्टर सरकार के स्मार्ट नगर बनाने का दावा मात्र एक ढोंग प्रतित होता है।

प्रधानमंत्री मोदी 2019 में होने वाले लोक सभा चुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों में गहमा-गहमी के बीच मोदी जी ने चुपके से राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नीरा राडिया वाले केस में शामिल सुनील अरोड़ा की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति कर दी है। सुनील अरोड़ा राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे और तब सत्ता भाजपा के पास थी। उसी दौर में राजस्थान की कई जमीनें कुछ खास नौकरशाहों को नीरा राडिया के ज़रिए मुक्त या कौड़ियों के भाव बांटी गई थी जो टेलिफ़ोन टेपिंग में सामने आई है। सुनील अरोड़ा व नीरा राडिया की मिलीभगत की 'नीरा राडिया कांड के दाग़ी सुनील अरोड़ा को बनाया मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त' में परतें खोली गई हैं। अरोड़ा की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से मोदीजी के 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' दावे की पोल खुल गई है।

शहर की डिस्पेंसरी से रेफ़र होकर आने वाले मरीज़ों को सेक्टर 8 के ईएसआई अस्पताल में खट्टर सरकार की लापरवाही के कारण बदहाली का सामना करना पड़ाता है, जिसकी 'ईएसआई अस्पताल सेक्टर 8 में 18 साल से अल्ट्रा साऊंड मशीन नहीं, मरीज़ भटकने को मज़बूर' में समीक्षा की गई है। इस अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ़ व उपकरणों का अभाव बना रहता है। फ़िलहाल 50 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन वहां सिर्फ़ 15 डॉक्टर काम कर रहे हैं और 18 साल से अल्ट्रा साऊंड मशीन भी नहीं खरीदी गई है। चिकित्सा के नाम पर 'आयुष्मान भारत' की नाटकबाज़ी करने वाली सरकार की बदौलत यह अस्पताल इलाज करने की बजाए मात्र रेफ़र करने के लिये रह गया है।

राष्ट्रीय एकता व हिन्दू-मुस्लिम एकता के पैरोकार स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, जिसका 'आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद' में विवेचन किया गया है। मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत तथा पाकिस्तान के रूप में अलग राष्ट्र बनाने की मांग का सदैव विरोध किया था। उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों को सलाह दी थी कि वे पाकिस्तान की तरफ़ पलायन न करें, क्योंकि वहां पहले से रहने वाले लोग जब अपनी क्षेत्रीय पहचान के लिये उठ खड़े होंगे तब वे भारत से जाने वाले लोगों से बिन बुलाये मेहमान की तरह पेश आएंगे। पाकिस्तान की घटनाओं ने मौलाना आज़ाद की भविष्यवाणी को सत्य साबित कर दिया है। धर्म से आधारित राजनीति करने वालों को इससे सबक लेना चाहिये।

नगर निगम फ़रीदाबाद के कमिश्नर मोहम्मद शाइन के प्रयत्नों से निगम में अनेक घोटाले सामने आए हैं, जिनकी 'नगर निगम में प्रकट हो रहे अरबों के घोटाले, क्या रिकवरी हो पायेगी? तथा 'निगमायुक्त शाइन हरामखोरी व रिश्वतखोरी का विकल्प मानते हैं सलाहकार को' में पोल खोली गई है। नगर निगम अधिकारियों की हरामखोरी व रिश्वतखोरी के अनेक मामलों का विस्तृत विवरण 'मज़दूर मोर्चा' के विभिन्न अंकों में पहले भी प्रकाशित हो चुका है परंतु उनके खिलाफ़ कभी कोई कार्यवाही नही की गई। देखना है कि क्या कमिश्नर शाइन इन घोटालों के आरोपियों को वाजिब सजा दिला पायेंगे?

'देश का आधे एटीएम बन्द होने का भाजपाई-उद्योगपति कनेक्शन' में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अप्रैल 2018 में एटीएम सर्विस प्रोवाइडर और उनके कॉन्ट्रैक्टर पर लागू किए नियमों का पर्दाफ़ाश किया गया है। एटीएम बिजनेस में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो 20 साल से भी अधिक समय से बैंकों और एटीएम को कैश सप्लाई का काम कर रही हैं। परंतु अब बड़ी कंपनियों ने मोदी सरकार पर दबाव डालकर नियमों में बदलाव करवाया है जिसके अनुसार एटीएम सर्विस प्रोवाइडर की कुल सम्पत्ति कम से कम 100 करोड़ रुपये तथा उसके पास 300 कैश वैन का बेड़ा होना जरूरी है। इन नियमों को पूरा करने वाली सिर्फ़ दो-तीन कंपनी हैं जिनमें एक बिहार से सबसे अमीर भाजपा सांसद आर.के.सिन्हा है। मोदी सरकार की बदौलत पुरानी छोटी कंपनियां इस कारोबार से बाहर हो जाएंगी और बड़े पूंजीपतियों को लाभ होगा।

गरीबी, भूख, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा व बेघर लोगों के लिये मकानों की समस्या को नज़र-अंदाज करते हुये मोदी सरकार द्वारा पटेल, शिवाजी व राम की मूर्ति बनाने व बुलेट ट्रेन चलाने पर अनाप-शनाप खर्चा करने और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग राज करने तथा राम मंदिर बनाने का नाम पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की नीति पर 'गरीब को क्या चाहिये' में उचित तंज कसा गया है।

धर्म की आड़ में व राम मंदिर के नाम से साम्प्रदायिक तनाव फैलाने, कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने तथा जुमलेबाजी व सब्जबाग दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की प्रधानमंत्री मोदी की कला और जुमलेबाजी से लोगों को मोदीजी के भाषणों की शैली पर सहस्त्राब्दि के सबसे बौने लोग' कविता के जरिये उचित व्यंग्य किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान को दलित बताने पर 'कहां जा रहे हो हनुमान? ....प्रभु, मेरी कास्ट सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमैंट ने बना दी है, लाने जा रहा हूं।' तथा प्रधानमंत्री मोदी की कृषि नीति के कारण उत्पन्न कृषि संकट व किसानों की आत्महत्या पर 'कृषि!-प्रधान!-देश! कार्टूनों द्वारा उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।